भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3722
उत्तर देने की तारीख-25/03/2026

प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान किया जाना

3722 #**श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में कितनी प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई है;
(ख) क्या सरकार देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने वाली उन शास्त्रीय भाषाओं पर विशेष ध्यान दे रही है और क्या प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए लगातार काम कर रही है; और
(ग) शास्त्रीय भाषाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने ग्यारह भाषाओं अर्थात तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम, उड़िया, असमिया, बंगाली, मराठी, पालि और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। शास्त्रीय भाषाओं और अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए, सरकार द्वारा समर्पित संस्थाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से कई पहलें शुरू की गई हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरू, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो शास्त्रीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, प्रलेखन, प्रचार और शिक्षण का कार्य करता है।

सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए सीआईआईएल के अंतर्गत चार उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की है, नामत: शास्त्रीय कन्नड़ अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएससीके), शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएससीटी), शास्त्रीय उड़िया अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएससीओ) और शास्त्रीय मलयालम अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

(सीईएससीएम)। ये केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं और शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, शास्त्रीय तमिल के अनुसंधान, संरक्षण और प्रसार से संबंधित गतिविधियां करता है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का कार्य सरकार द्वारा इसके शिक्षण, संरक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल देती हैं।

*****